भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4181
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

4181. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से दक्षिण कन्नड़ जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण की गई और निर्माणाधीन सड़कों की कुल लंबाई (किमी में) का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इन स्वीकृत सड़कों के पूरा होने में कोई देरी हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने सुल्लिया , बेलथांगडी और पुत्तूर के कम जनसंख्या घनत्व वाले तालुकों में बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इन सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और रिपोर्ट तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि क्षतिग्रस्त सड़कों की पुनः मरम्मत करके उन्हें उचित स्थिति में लाया जाए; और
(च) दक्षिण कन्नड़ में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें हरित निर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है और उनके तहत निर्मित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- III के तहत 2020 से कर्नाटक राज्य को 2,571 किलोमीटर लंबाई की कुल 424 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इसी अवधि के दौरान , 5,396 किलोमीटर लंबाई की कुल 784 सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं और 156 किलोमीटर लंबाई की 81 सड़कें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में निर्माण के लिए शेष हैं।
कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में, वर्ष 2020 से अभी तक 71 किलोमीटर लंबाई की कुल 11 सड़कों को मंजूरी दी गई है। इसी अवधि के दौरान , 172 किलोमीटर लंबाई की 21 सड़कें निर्मित हो चुकी हैं और 5.75 किलोमीटर लंबाई की 2 सड़कें विभिन्न चरणों में निर्माण के लिए शेष हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में 21 स्वीकृत सड़कों, जिसमें सुल्लिया, बेलथांगडी और पुत्तूर ब्लॉक में स्वीकृत परियोजनाएँ शामिल हैं, के निर्माण में देरी हुई है जो भूमि संबंधी समस्याओं , उपयोग में कमी, प्रतिकूल मौसम, निर्माण सामग्री की कमी, ठेकेदार द्वारा धीमी गति से निर्माण और कार्यस्थल पर अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कारकों के कारण हुई हैं। राज्य ने सूचित किया है कि सभी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

'ग्रामीण सड़कें' राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़कों का समय पर निर्माण कार्य पूरा करना संबंधित राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है। विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और अधिकार प्राप्त समितियों की बैठकों के माध्यम से राज्य सरकारों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों को समय

पर पूरा करने के लिए आवश्यक उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। पीएमजीएसवाई सड़कों के समय पर निर्माण कार्य पूरा करने में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:

i. राज्यों से निष्पादन क्षमता और अनुबंध क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।
ii. बोली दस्तावेज प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
iii. क्षमता निर्माण के लिए फील्ड इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
iv. विभिन्न क्षेत्रों में उस जोन के राज्यों के समूह के लिए नियमित अंतराल पर वास्तविक एवं वित्तीय मापदंडों की नियमित एवं संरचित समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ): पीएमजीएसवाई निर्माण के दौरान सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन तंत्र की परिकल्पना करती है। इस तंत्र का पहला स्तर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर पर आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण है। दूसरा स्तर राज्य स्तर पर राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम) के माध्यम से एक निष्पक्ष गुणवत्ता निगरानी के रूप में संरचित है , जिसमें पीएमजीएसवाई कार्यों के नियमित निरीक्षण का प्रावधान है। तीसरा स्तर केंद्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र है। इस स्तर के अंतर्गत , पीएमजीएसवाई सड़कों के निरीक्षण के लिए यादृच्छिक रूप से चुने गए निष्पक्ष राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) नियुक्त किए जाते हैं। गुणवत्ता निगरानी में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे स्तर के निष्पक्ष निगरानीकर्ता प्रत्येक निरीक्षण किए गए सड़क कार्य के लिए कार्य स्थल पर कम से कम 10 डिजिटल तस्वीरें लें , जिसमें एक क्षेत्रीय प्रयोगशाला की तस्वीर भी शामिल हो। और निरीक्षण रिपोर्ट पीएमजीएसवाई कार्यक्रम प्रबंधन एवं निगरानी वेबसाइट अर्थात ओएमएमएएस पर अपलोड करें , ताकि कार्यक्रम के तहत किए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को आम जनता के लिए देखना आसान हो सके। साथ ही, उक्त निरीक्षण रिपोर्ट का सार वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

दक्षिण कन्नड़ ज़िले में अप्रैल , 2020 से जुलाई, 2025 तक एनक्यूएम द्वारा कुल 24 निरीक्षण किए गए, जिनमें से 2 निरीक्षण पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं पर और शेष 22 निरीक्षण चालू परियोजनाओं पर किए गए। एनक्यूएम द्वारा सभी निरीक्षण संतोषजनक पाए गए।

ई-मार्ग (ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव) अर्थात पीएमजीएसवाई सड़कों के एमआईएस के रखरखाव के माध्यम से , पारदर्शी और सत्यापन योग्य रखरखाव आंकड़ों के संग्रह के लिए रखरखावाधीन सड़कों के सभी निरीक्षण आंकड़ों , साथ ही जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प्ड तस्वीरों को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रणाली वास्तविक समय निगरानी को सक्षम बनाती है , इससे दोषों की शीघ्र पहचान हो पाती है , और यह सुनिश्चित करती है कि बिना किसी देरी के सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। शुरुआत के बाद से , ई-मार्ग का उपयोग पूरे पाँच वर्षीय दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान सड़कों की निगरानी के लिए व्यापक रूप से किया गया है। दक्षिण कन्नड़ जिले में 21 पूर्ण सड़कों का रखरखाव भी ई-मार्ग पर दर्ज किया जाता है।

पीएमजीएसवाई सड़कों को होने वाली क्षति के मामले में , जो नियमित रखरखाव में शामिल नहीं है , राज्य आवश्यक मरम्मत उपाय करते हैं और ई-मार्ग पर नियमित रखरखाव पुनः शुरू करते हैं।

(च): कर्नाटक राज्य में , हरित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत स्वीकृत कुल 1,963 किलोमीटर सड़क लंबाई में से, 1,937 किलोमीटर सड़क राज्य द्वारा पहले ही निर्मित कर ली गई है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़

जिले में, हरित प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कुल 46 किलोमीटर सड़क लंबाई स्वीकृत की गई है, जो पहले ही पूर्ण हो चुकी है।

*****